स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA

स्वच्छता समाचार

नवंबर 2024

स्वच्छ भारत मिशन

ग्रामीण

केंद्रीय मंत्री की कलम से

स्वच्छता एक सेवा ही नहीं वरन, यह एक ऐसा आंदोलन है जो समुदायों का उत्थान करता है और जीवन में बदलाव लाता है। आगामी विश्व शौचालय दिवस हमें ग्रामीण भारत में सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता समाधान सुनिश्चित करने में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की महत्वपूर्ण भूमिका को एक बार फिर से स्थापित और पुष्ट करता है। हम जो काम करते हैं उसकी जड़ें सामुदायिक भागीदारी में गहराई से निहित हैं-आमजन अपने पर्यावरण की जिम्मेदारी लेने के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। इस अभियान में न केवल जमीनी स्तर से अभूतपूर्व भागीदारी देखी गई है, वरन उन प्रभावशाली लोगों का सहयोग और भी मिलता रहा है जो स्वच्छता और गरिमा के संदेश का प्रसार करते हैं। एक साथ मिलकर, हम एक स्वस्थ, अधिक लचीले भारत का निर्माण कर रहे हैं।

श्री सी. आर. पाटिल
केंद्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

केंद्रीय राज्य मंत्री की कलम से

स्वच्छता एक ऐसी सतत् यात्रा है जिसके लिए समाज के सभी स्तरों पर स्वच्छता की संस्कृति को शामिल करने की आवश्यकता है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से, हम नियमित अभियानों द्वारा बुनियादी ढांचे से अधिक निर्माण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रहे हैं जो स्वच्छता को स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक मानती है। चूंकि कचरा निरंतर निकलता रहता है, अत: स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने के हमारे प्रयास घरों से लेकर स्कूलों और कार्यस्थलों के साथ-साथ अन्य स्थानों तक अर्थात् भारत के कोने-कोने तक पहुंचने चाहिए। यह कार्यक्रम स्वच्छता की दिशा में सामूहिक सहयोग के माध्यम से गति देने में सक्षम रहा है। इससे भविष्य की पीढ़ियों को लाभान्वित करने वाली स्वच्छता की स्थायी संस्कृति का निर्माण होगा।

श्री वी. सोमण्णा
केंद्रीय राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय

सचिव की कलम से

स्वच्छता, एक मिशन के रूप में, गतिशील है और यह हमारे समाज की बदलती जरूरतों के साथ विकसित हो रही है। खुले में शौच मुक्त (ODF) स्थिति प्राप्त करने के महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के साथ शुरू हुआ कार्य अब मानसिकता को बदलने और स्थायी प्रथाओं को सुनिश्चित करने तथा विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने पर केंद्रित एक बड़े आंदोलन में बदल गया है। स्वच्छ भारत मिशन केवल बुनियादी ढांचे तक ही सीमित नहीं है; इसका उद्देश्य भागीदारी को बढ़ावा देने, युवाओं को इस मिशन में शामिल करने और सभी के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ भविष्य बनाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप कार्य करना है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, यह मिशन एक स्वच्छ और समृद्ध भारत के दृष्टिकोण के साथ स्वयं को नई चुनौतियों और मांगों के अनुकूल ढ़ालता रहेगा।

श्री अशोक कुमार कालुराम मीना
सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

मिशन निदेशक की कलम से

ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में हमने जो काम किया है, उसे 5Ps – People (आमजन), Participation (भागीदारी), Partnership (साझेदारी), Processes (प्रक्रियाओं) और Performance (कार्यनिष्पादन) द्वारा निर्देशित किया गया है। जहां शौचालयों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई है, वहीं हमारा ध्यान इनके निरंतर उपयोग, पहुंच और सभी तक पहुंचने वाली प्रणालियों को सुनिश्चित करने की दिशा में भी केंद्रित रहा। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस मिशन में सबसे आगे हैं। वे इसे आगे बढ़ाने के लिए समुदायों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हर स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देकर, हम एक स्वस्थ और अधिक समावेशी भारत का निर्माण करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के व्यापक लक्ष्यों और सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप सतत स्वच्छता के लिए प्रतिबद्ध हैं।

श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM-G), पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय

कार्यक्रम की उपलब्धियां

15 नवंबर, 2024 तक

ODF PLUS

भारत के **5.57 लाख** से अधिक बसे हुए गांवों ने स्वयं को ODF Plus घोषित किया है।

- उदीयमान: **1,82, 665**
- उज्ज्वल: **17,189**
- उत्कृष्ट: **3,58,024**
- सत्यापित: **1,76,154**

4,42,871 गांवों में ठोस कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है
5,06,838 गांवों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था है
1,209 बायोगैस संयंत्र पंजीकृत
859 कार्यशील बायोगैस संयंत्र
67 कार्यपूर्ण बायोगैस संयंत्र
4,088 ब्लॉकों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन की व्यवस्था है

स्वच्छता पखवाड़ा

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

- विभिन्न कार्यालयों द्वारा कार्यालयों की सफाई

नागर विमानन मंत्रालय

- SHS के दौरान, विभिन्न कार्यालयों में स्वच्छता अभियान चलाए गए
- JDG द्वारा DGCA मुख्यालय लॉन में सभी अधिकारियों के लिए स्वच्छता शपथ समारोह

रेल मंत्रालय

- SHS 2024 के दौरान विभिन्न स्थानों पर स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता विषय के साथ स्वच्छता जागरूकता रैलियां
- चिह्नित स्वच्छता लक्ष्य इकाइयों (CTU) के तहत विभिन्न स्थानों की सफाई जिनके लिए कचरे के उचित निपटान, पेड़ों/घास की छंटाई (ट्रिमिंग), स्थापना और कूड़े-कचरे वाले क्षेत्रों की सफाई की आवश्यकता होती है
- विभिन्न स्थानों पर कचरा प्रबंधन के संबंध में सेमिनार आयोजित किए गए
- वर्कशॉप स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ का मेडिकल चेकअप किया गया
- बायकुल्ला में "स्वच्छ जागरूकता रैली" का आयोजन; तिरुपति में चाय बूथों के पास कूड़ेदान लगाना
- BB मंडल के विभिन्न स्टेशनों पर स्वच्छ नीर कार्यक्रम का आयोजन
- EMU कुर्ला कार शेड ने बड़े पैमाने पर सफाई अभियान चलाया और कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल को साफ रखने के लिए प्रेरित करने के लिए एक मानव श्रृंखला बनाई
- शून्य कचरा वाले स्वच्छ स्टेशन प्लेटफॉर्म और सभी स्टेशनों की गंदगी मुक्त गहन सफाई। कचरे का पृथक्करण

ग्रामीण विकास मंत्रालय

- शौचालयों, सामान्य गलियारों, और सीढ़ी, लिफ्ट आदि जैसे सामान्य क्षेत्रों सहित कार्यालय परिसरों का रखरखाव और सफाई
- कृषि भवन स्थित उन्नति सम्मेलन कक्ष में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।
- कर्मचारियों द्वारा तालाब की सफाई पर केंद्रित विशेष सफाई अभियान चलाया गया
- विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण अभियान चलाया गया
- स्वच्छ जल, उचित स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन के महत्व पर विशेष सत्र आयोजित किए गए

पहियों से संपन्नता: (एम्पावर्ड बाय व्हील्स) बस्तर, छत्तीसगढ़ में बाधाओं को तोड़ने वाली एक सफाई मित्र कहानी

बस्तर की अडवाल ग्राम पंचायत के अडवाल गांव की चालीसवें वर्ष की प्रारंभिक अवस्था महिला सुभद्रा भारती को लगातार वित्तीय संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिससे उनके लिए दिन-प्रतिदिन के खर्चों का प्रबंधन करना मुश्किल हो गया। HDFC बैंक-CEE में कार्यरत एक स्थानीय स्वयं सहायता समूह (SHG) से उसके दोस्त ने बस्तर में सामग्री संग्रहण सुविधा (MRF) की स्थापना की, उनकी क्षमता को पहचानते हुए, अवसरों की तलाश करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया और उन्हें स्थायी आय अर्जित करने के लिए बस्तर जिला प्रशासन द्वारा प्रदान किए जा रहे ई-रिक्शा चलाने के लिए सीखने हेतु प्रोत्साहित किया।

उन्होंने कचरा संग्रह के लिए ई-रिक्शा ड्राइविंग का 6-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरा किया, जिसमें ड्राइविंग कौशल, यातायात नियम, वाहन रखरखाव और ग्राहक सेवा शामिल थी। सुभद्रा मार्च 2023 से जुलाई 2024 तक 12 मीट्रिक टन सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र करने वाले दो सफाई मित्रों की मदद से गांव अडवाल में प्रति सप्ताह लगभग 35 किलोमीटर ई-रिक्शा चलाती रही हैं। कचरे को पंचायत शेड में संग्रहीत किया जाता है, जिसमें एक चार्जिंग पॉइंट भी होता है जहां सुभद्रा साप्ताहिक रूप से रिक्शा चार्ज करती हैं।

वर्तमान में, इस परियोजना के तहत 63 गांवों और 56 ग्राम पंचायतों में घरों से हर 6 दिनों में सूखा और प्लास्टिक कचरा एकत्र किया जा रहा है। इस पहल में 436 सदस्यों के साथ 83 SHG शामिल हैं जो MRF में अपशिष्ट संग्रह और पृथक्करण का प्रबंधन करते हैं। सुभद्रा सहित सफल मित्र, कचरा ढोने के लिए हाथ गाड़ी और ई-रिक्शा का उपयोग करते हैं, और वे सामाजिक मानचित्रण आरेखों के माध्यम से प्रलेखित सहयोगपरक निर्णय लेते हैं। यह कार्यक्रम इन सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता शुल्क एकत्र करने की समस्या का समाधान कर रहा है जो SBM दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं जो कार्यक्रम स्थिरता पर केंद्रित हैं।

SBM-ग्रामीण के तहत जिला प्रशासन ने SHG को 82 अत्याधुनिक ई-रिक्शा प्रदान किए हैं, जिन्हें सूखे और गीले कचरे को अलग-अलग करने, संग्रह दक्षता बढ़ाने और स्थायी आजीविका बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सुभद्रा सहित सफाई मित्रों ने ई-रिक्शा को सुरक्षित रूप से चलाने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

स्वच्छता ही सेवा 2024 के दौरान सफाई मित्र सुरक्षा शिविरों/गरिमा शिविरों के माध्यम से स्वच्छता कर्मचारियों का सशक्तिकरण

स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2024 अभियान के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में, स्वच्छता कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ाने के लिए देश भर में गरिमा शिविर आयोजित किए जाने होते हैं, जिन्हें सफाई मित्र सुरक्षा शिविर के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष के SHS अभियान का विषय "स्वभाव स्वच्छता- संस्कार स्वच्छता" का उद्देश्य स्वच्छता में योगदान देने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिकों को शामिल करना है।

गरिमा शिविर SHS 2024 अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। इन्हें स्वच्छता कर्मचारियों को विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर सशक्त बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। चरणों में आयोजित ये शिविर व्यवस्थित रूप से स्वच्छता कर्मचारियों की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करेंगे और व्यापक विकास एजेंडे में उनका समावेश सुनिश्चित करेंगे। प्रभावी कवरेज और अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इन शिविरों के कार्यान्वयन को अलग-अलग चरणों में रूपरेखा तैयार की गई है:

चरण 1: जागरूकता और नामांकन: स्वच्छता कर्मचारियों के लिए उपलब्ध विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
चरण 2: योजना एकीकरण और पहुंच: स्वच्छता कर्मचारियों को संबंधित सरकारी योजनाओं में नामांकन में सहायता प्रदान की जाएगी। उन्हें आवास, पानी, स्वच्छता, बिजली, स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
चरण 3: निगरानी और मूल्यांकन: नामांकित स्वच्छता कर्मचारियों की निगरानी पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें योजनाओं का लाभ प्राप्त हो।

कवर किए गए प्रमुख कल्याण क्षेत्र: इन गरिमा शिविरों में भाग लेने वाले स्वच्छता कर्मचारियों को प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार कई योजनाओं में नामांकन के लिए निर्देशित किया जाएगा। गरिमा शिविर स्वच्छता कर्मचारियों के योगदान को मान्यता प्रदान करने और उन्हें विकसित होने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है। ये शिविर उन लोगों के लिए गरिमा और सम्मान बहाल करते हैं जो सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं।

*अधिक पढ़ने के लिए, **यहां क्लिक करें***

समुदाय द्वारा कचरे को एक संसाधन के रूप में देखना: नारियल पुनर्चक्रण पहल

ओडिशा के गंजाम जिले के हिंजिलिकट ब्लॉक, में, 89 गांवों और पंचायतों ने सामग्री संग्रहण सुविधा (MRF) चलाने के लिए सेवा प्रदाता, कोर के सहयोग से जिला परिषद और HDFC बैंक के साथ हाथ मिलाया है। सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन (CEE) के नेतृत्व में यह पहल, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत "सूखे और प्लास्टिक कचरे से मुक्त ग्रामीण और शहरी परिदृश्य" परियोजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नारियल कचरे की समस्या का समाधान करना है, जो इस क्षेत्र में बढ़ते पर्यावरणीय खतरे के रूप में सामने आया है।

पिछले दो वर्षों से, CEE और CORE, 105 गांवों में प्लास्टिक और सूखे कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें 1,100 टन प्लास्टिक जमा हो रहा है। हिंजिलिकट के नुआगाडा में MRF को उन स्थानीय महिलाओं या सफाई मित्रों द्वारा चलाया जाता है, जिन्हें कोर द्वारा प्रशिक्षित और सहयोग प्रदान किया जाता है। ये महिलाएं CEE और CORE के मार्गदर्शन के साथ प्रति दिन 3 से 3.5 टन कचरे को संभालते हुए, सूखे और प्लास्टिक कचरे को संसाधित करने वाली विभिन्न मशीनों का प्रबंधन करती हैं।

गंजाम नारियल का एक प्रमुख उत्पादक जिला है, जहां घरों, बाजारों और धार्मिक समारोहों से निकले नारियल के कचरे के निपटान की चुनौती है। इसके समाधान के लिए, महिला स्वयं सहायता समूहों (SHG) ने विभिन्न स्रोतों से नारियल एकत्र करने और उन्हें MRF पर संसाधित करने का कार्य शुरू किया है। नारियल की भूसी और गोले को काटकर, यह सुविधा कॉयर, भूसी और जैविक खाद (कोकोपीट) जैसे उप-उत्पाद उत्पन्न करती है, जिन्हें बाद में आजीविका उत्पादों के रूप में बेचा जाता है।

यह पहल न केवल पर्यावरण प्रदूषण को कम करती है और बंद जल निकासी प्रणालियों को कम करती है, बल्कि नारियल कचरे को सड़ने से हानिकारक मीथेन गैस निकलने को भी रोकती है। यह परियोजना नगरपालिका कचरा प्रबंधन प्रणालियों पर बोझ को कम करने में मदद करती है और समुदाय में महिलाओं के लिए आय के अवसर सृजित करती है। MRF उन्नत मशीनों से युक्त है और नारियल के कचरे को मूल्यवान उत्पादों में संसाधित किया जाता है, जिससे सफाई मित्रों की अतिरिक्त आय होती है। साथ ही, नारियल कचरा समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान होता है।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

गुजरात ने SBM की 10वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय प्लास्टिक कचरा प्रबंधन प्रशिक्षण की मेजबानी की

स्वच्छ भारत मिशन (SBM) की 10वीं वर्षगांठ मनाने के लिए और स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत, गुजरात सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन (PWM) पर केंद्रित एक महत्वपूर्ण पहल की। श्रीमती मनीषा चंद्रा आईएएस, आयुक्त एवं सचिव, श्री सुजल मयात्रा, आईएएस, मिशन निदेशक SBM-G, और श्री विशाल गुप्ता, आईएएस, अपर आयुक्त SBM-G और ग्रामीण विकास के नेतृत्व में, राज्य ने जमीनी स्तर पर PWM प्रथाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एक जिला-व्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

SBM-G गुजरात ने पर्यावरण शिक्षा केंद्र (CEE), गुजरात के सहयोग से 30 सितंबर, 2024 को 1,550 से अधिक अधिकारियों और हितधारकों की सक्रिय भागीदारी के साथ सभी 33 जिलों में "स्वच्छता वार्ता" आयोजित की। इनमें ब्लॉक पंचायत के निर्वाचित सदस्य, जिला स्वच्छ भारत मिशन की टीमें, सरपंच, पंचायत सचिव, मनरेगा कर्मचारी और स्वयं सहायता समूहों (SHG) के सदस्य शामिल थे। इसका उद्देश्य PWM के विशिष्ट महत्व पर स्थानीय हितधारकों को शामिल करना था, जिसमें कचरा पृथक्करण, स्थायी निपटान और उचित कचरा प्रबंधन के माध्यम से ग्रामीण समुदायों के लिए सृजित किए जा सकने वाले आर्थिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

राजसमंद, राजस्थान का कचरे से कला नवाचार: प्लास्टिक को एक अधिक स्वच्छ, हरित भविष्य में बदलना

राजसमंद जिला स्वच्छ भारत मिशन के स्वच्छता ही सेवा (SHS) 2024 अभियान के तहत 50 लाख एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक बैग को 1.25 लाख प्लास्टिक की बोतलों में पैक करके स्थायी कचरा प्रबंधन में नई नई संभावना खोज रहा है।

यह नवाचार जिले की स्वच्छता की 4P अवधारणा: प्लास्टिक को हटाने, पेड़ लगाने, पानी बचाने और पर्यावरण को सुंदर बनाने का हिस्सा है जिसे SHS 2024 के तहत में लागू किया गया था।

जिला कलेक्टर श्री बाल मुकुंद असावा के नेतृत्व में, यह अभियान खुले में शौच मुक्त (ODF) प्लस मॉडल गांवों में दर्शनीय स्वच्छता के लिए प्लास्टिक कचरे को व्यावहारिक, पर्यावरण के अनुकूल समाधान में बदलने पर केंद्रित है।

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक से भरी बोतलों का उपयोग "वेस्ट टू आर्ट" पहल में किया जा रहा है, जो विभिन्न ग्राम पंचायतों में स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत शुरू हुआ है। SBM-G के जिला परियोजना समन्वयक नाना लाल साल्वी द्वारा समन्वित पहल में इन बोतलों को कलात्मक कृतियों जैसे प्लेटफार्म, ट्री गार्ड, बेंच और अन्य संरचनाओं में बदलना शामिल है। पर्यावरण संरक्षण और सौंदर्यीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह अभिनव प्रायोगिक परियोजना लागू की जा रही है।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

जिम्मेदार पर्यटन में केरल की छलांग: स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली

जब पर्यटन की बात आती है तो केरल हमेशा अग्रणी रहा है, और अब राज्य ने स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग (SGLR) प्रणाली के साथ जिम्मेदारीपूर्ण पर्यटन में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) और पर्यटन मंत्रालय के साथ भागीदारी में यह पहल, आतिथ्य सुविधाओं में स्वच्छता मानकों के महत्व पर जोर देती है।

स्वच्छता मानकों में अग्रणी

केरल का सक्रिय दृष्टिकोण उपयोगकर्ता के अनुकूल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत के साथ अग्रणी है, जिससे आतिथ्य सुविधाओं के लिए उनके स्वच्छता मानकों का आकलन करना आसान हो जाता है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, पंजीकृत उपयोगकर्ता स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग प्रणाली के अनुपालन को चिह्नित करते हुए स्व-मूल्यांकन कर सकते हैं। यह सरल प्रक्रिया सुविधाओं को आसानी से यह मापने की अनुमति देती है कि स्वच्छता मानकों को बनाए रखने में उनका स्थान क्या है।

प्रथम चरण के परिणाम

पहले चरण में, केरल में कुल 425 आतिथ्य सुविधाओं ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत 680 स्व-मूल्यांकन में से ग्रीन लीफ रेटिंग अर्जित की। इनमें से, 96 सुविधाएं प्रारंभिक स्व-मूल्यांकन पास नहीं कर पाई और 159 प्रमाणन के लिए अर्हता प्राप्त करने में विफल रहीं क्योंकि वे 100 अंकों के न्यूनतम आवश्यक स्कोर को पूरा नहीं करती थीं। तथापि, सत्यापन चरण में 67 सुविधाओं ने प्रतिष्ठित 5-लीफ रेटिंग हासिल की, अन्य ने 3 या 1 लीट रेटिंग हासिल की, जो अनुपालन के विभिन्न स्तरों को दर्शाती है।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत बिल्लोरी, छत्तीसगढ़ में ग्राम जागरूकता और सामाजिक मानचित्रण सत्र का आयोजन

18 सितंबर, 2024 को स्वच्छता ही सेवा 2024 के बैनर तले बस्तर, छत्तीसगढ़ के जिला प्रशासन ने CSR और RWPF पार्टनर के सहयोग से ग्राम पंचायत बिल्लोरी-01 में ग्राम जागरूकता बैठक और सामाजिक मानचित्रण सत्र का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को SHS 2024 अभियान के तहत सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और स्थानीय स्वच्छता प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया था। मुख्य उद्देश्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सामुदायिक आवश्यकताओं को समझना: भागीदारी चर्चाओं और मानचित्रण अभ्यासों के माध्यम से समुदाय की विशिष्ट स्वच्छता चुनौतियों, आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करना।
- सामुदायिक भागीदारी बढ़ाना: आयोजना और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में समुदाय के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना, स्वच्छता पहल के स्वामित्व को बढ़ावा देना।
- डेटा की कल्पना करना: समुदाय के परिदृश्य का एक ऐसा आभासी चित्र बनाना, जिससे स्थानिक संबंधों को समझना और स्वच्छता सेवाओं में अंतराल की पहचान करना आसान हो सके।

इस कार्यक्रम में सरपंच, ग्राम सचिव, ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों और SBM ग्रामीण सहित समुदाय के 50 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

बिहार: SBM-G के माध्यम से ग्लोबल हैंडवाशिंग-डे के बारे में जागरूकता बढ़ाना

ग्लोबल हैंडवाशिंग-डे (15 अक्टूबर) पर, बिहार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) के तहत राज्यव्यापी हाथ स्वच्छता जागरूकता अभियान शुरू किया। इस अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य के आवश्यक घटकों के रूप में स्वच्छता और हाथ धोने के बीच महत्वपूर्ण संबंध पर जोर देना है। स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों, अस्पतालों और समुदायों में, साबुन और पानी से हाथ धोने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। पूरे राज्य में 75,000 से अधिक स्कूलों और 60,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में हाथ धोने के कार्यक्रम और प्रदर्शन आयोजित किए गए।

हाथ धोने की उचित तकनीक और महत्वपूर्ण समय के संबंध में ये प्रदर्शन आयोजित किए गए जब यह सबसे महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि भोजन से पहले और शौचालय का उपयोग करने के बाद। इन प्रदर्शनों का नेतृत्व शिक्षकों और अग्रणी कार्यकर्ताओं ने किया।

हाथ की स्वच्छता उन बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं बनी हुई हैं। बिहार में चलाया गया अभियान, SBMG के उन व्यापक उद्देश्यों के अनुरूप है, जो स्थायी स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

DDWS ने 28 अक्टूबर को WASH के लिए नेशनल विज़निंग वर्कशॉप का आयोजन किया

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) ने हाल ही में भारत मंडपम, नई दिल्ली में एक परिवर्तनकारी कार्यशाला आयोजित की, जिसमें उपलब्धियों का आकलन करने और जल, स्वच्छता और साफ-सफाई (WASH) में स्थायी सामुदायिक सहभागिता से संबंधित पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए विशेषज्ञों और नेताओं को एक मंच पर लाया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBMG) के दस वर्षों और जल जीवन मिशन (JJM) के पांच वर्षों को चिह्नित करने वाली इस राष्ट्रीय विजन कार्यशाला का उद्देश्य भविष्य की रणनीतियों को राष्ट्रीय विकास लक्ष्यों के अनुरूप बनाना है।

इस कार्यक्रम में DDWS की सचिव श्रीमती विनी महाजन; श्री अशोक के. के. मीणा, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD), DDWS; डॉ. चन्द्रा भूषण कुमार, अपर सचिव एवं मिशन निदेशक, NJJM; श्रीमती ऋचा मिश्रा, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, DDWS; श्री जितेन्द्र श्रीवास्तव, मिशन निदेशक एवं संयुक्त सचिव, SBM-G; और श्रीमती स्वाति मीणा नाइक, संयुक्त सचिव, NJJM, सचिवों, मिशन निदेशकों, इंजीनियर-इन-चीफ सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने कार्यशाला में भाग लिया। यह राष्ट्रव्यापी वॉश उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कार्यशाला में भावी रणनीतियों को परिष्कृत करते हुए प्रगति का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें प्रभावी सामुदायिक भागीदारी पर व्यापक जोर दिया गया। अधिकारियों ने भारत के वॉश परिदृश्य को मूर्त रूप देने और SBM और JJM को व्यापक विकास उद्देश्यों के साथ संरेखित करने में श्रीमती विनी महाजन की महत्वपूर्ण भूमिका की भूरि-भूरि प्रशंसा की।

अधिक पढ़ने के लिए, ***यहां क्लिक करें***

राज्य के झरोखे से - हिमाचल प्रदेश का ग्रामीण प्लास्टिक कचरा समाधान: एक समुदाय-केंद्रित मॉडल

राघव शर्मा,
मिशन निदेशक

हिमाचल प्रदेश प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में एक उदाहरण स्थापित कर रहा है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कचरे हेतु बुनियादी ढांचा प्राय: सीमित होता है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-G) के तहत, ग्रामीण विकास विभाग ने एक पहल शुरू की है जो जमीनी स्तर पर प्लास्टिक कचरे से निपटती है।

यह प्रक्रिया ग्रामीण स्तर पर शुरू होती है, जहां पृथक्करण शेड प्लास्टिक को छांटने में मदद करते हैं। जिन वस्तुओं का पुनर्नवीनीकरण किया जा सकता है, जैसे PET बोतलें, वे स्थानीय पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजी जाती हैं। लेकिन जिद्दी, गैर-पुनर्नवीनीकरण प्लास्टिक का क्या होता है? यहीं से हिमाचल का मॉडल चमकता है। गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे को ब्लॉक स्तर पर प्लास्टिक कचरा प्रबंधन इकाइयों (PWMU) को निर्देशित किया जाता है। यहां, बेलर और श्रेडर से लैस, कचरे को स्थानीय सीमेंट संयंत्रों में रिफ्यूज-व्युत्पन्न ईंधन (RDF) के रूप में उपयोग करने के लिए तैयार किया जाता है।

राज्य, सीमेंट दिग्गजों-अंबुजा सीमेंट लिमिटेड और अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ हाथ मिलाने की प्रक्रिया में है ताकि इस प्लास्टिक कचरे को ईंधन के रूप में सह-संसाधित किया जा सके। सीमेंट के भट्ठों में उच्च तापमान पर, प्लास्टिक पूरी तरह से जल जाता है, न्यूनतम अवशेष छोड़ देता है और कोई हानिकारक प्रदूषक नहीं छोड़ता है। यह दृष्टिकोण लैंडफिल पर निर्भरता को कम करेगा, जीवाश्म ईंधन की बचत करेगा, और ग्रीनहाउस गैसों में कटौती के लिए भारत के लक्ष्यों के साथ संरेखित करेगा। अंबुजा सीमेंट संयंत्रों को कचरे के मुफ्त बैकहॉल परिवहन की पेशकश करके परियोजना में सहयोग भी करता है, जिससे प्रक्रिया किफायती हो जाती है।

यह भागीदारी केवल अपशिष्ट प्रबंधन तक ही सीमित नहीं रहेगी; यह अधिक स्वच्छ हिमाचल के प्रति प्रतिबद्धता है। इसका आशय यह भी है कि ग्रामीण समुदायों को रोजगार के अवसरों और एक बेहतर स्थानीय कचरा प्रणाली से लाभ होता है। कचरे को एक संसाधन में परिवर्तित करके, हिमाचल प्रदेश ने स्थिरता के लिए एक ऐसा व्यावहारिक, समुदाय-केंद्रित मॉडल तैयार किया है, जो पूरे भारत में इसी तरह के प्रयासों हेतु प्रेरित कर सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल भारत के स्थायी कचरा प्रबंधन लक्ष्यों का समर्थन करता है, बल्कि स्वच्छ भारत के दृष्टिकोण में भी सार्थक योगदान देता है, जो देश भर में स्वच्छ, हरियाली वाले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक अनुकरणीय पथ प्रशस्त करता है।

वर्ग पहेली

E	W	B	T	L	Z	E	R	O	W	A	S	T	E
L	L	U	S	S	A	N	I	T	A	T	I	O	N
B	F	T	L	N	O	E	G	D	U	L	S	G	N
A	T	R	E	S	A	A	A	G	U	O	P	A	R
D	A	E	E	G	E	O	K	O	S	U	P	I	T
A	E	N	W	P	A	F	A	P	I	T	R	P	F
R	P	C	E	B	N	W	E	N	I	R	T	A	L
G	L	H	T	I	I	B	E	O	L	T	I	U	P
E	A	I	T	O	B	E	I	S	G	P	R	E	E
D	S	N	A	F	I	S	T	A	D	R	T	A	I
O	T	G	H	U	A	P	H	Y	T	O	R	I	D
I	I	B	Y	E	G	O	B	A	R	D	H	A	N
B	C	L	D	L	R	E	T	A	W	Y	E	R	G
W	I	T	I	P	T	S	O	P	M	O	C	A	E

BIOFUEL | LATRINE | SOAKPIT | GOBARDHAN | SANITATION
GREYWATER | PLASTIC | SEWAGE | TRENCHING | ZEROWASTE
COMPOSTPIT | BIODEGRADABLE | SLUDGE | PHYTORID

स्वच्छता समाचार के अगले अंक में योगदान करने के लिए, हर महीने की 15 तारीख से पहले swachhbharat@gov.in पर अपनी प्रस्तुति साझा करें।

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION
MINISTRY OF JAL SHAKTI
GOVERNMENT OF INDIA
सत्यमेव जयते

विशेष सचिव का कार्यालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
भारत सरकार।

चौथी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली–110003
फोनः 011–24362192 | ईमेलः arun.baroka@nic.in